RNI No. RAJHIN/2001/05699

जनता की भावनाओं एवं आकांक्षाओं का एकमात्र समाचार-पत्र

हैलो सरकार

www.hellosarkar.com

पल-पल की टी.वी. एवं रेडियो खबरों के लिए लॉन ऑन करें- www.hellosarkar.com

हैलो सरकार समाचार पत्र में नियमित पाठक बनने, समाचार की प्रति मंगवाने व विज्ञापन देने हेतु सम्पर्क करें
फोनः 0141-2202717
मोः 9214203182
वाट्सप नं. 9928078717

सुविचार

खुद का अपमान कराके जीने से तो अच्छा मर जाना है क्योंकि प्राणों के त्यागने से केवल एक ही बार कष्ट होता है पर अपमानित होकर जीवित रहने से आजीवन दुःख होता है।

-चाणक्य

वर्ष-25 | अंक-262 | दैनिक प्रभात संस्करण | जयपुर, मंगलवार 26 मई, 2026 | पृष्ठ-4 | मूल्यः 2.50

जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए बनाएं बेहतर कार्ययोजना

अधिकारी टीम भावना के साथ करें कार्य-भजनलाल शर्मा

हैलो सरकार न्यूज

भरतपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को भरतपुर में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि भरतपुर हमारी ऐतिहासिक विरासत है, इसलिए विकास और धरोहर संरक्षण के कार्य बेहतर कार्ययोजना के साथ सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने के साथ ही फील्ड विजिट बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भीषण गर्मी के दृष्टिगत पेयजल, बिजली और चिकित्सा व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जाए, ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में टैंकर व्यवस्था तथा पेयजल आपूर्ति को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

साथ ही, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को विभागीय योजनाओं में लंबित प्रकरणों के संदर्भ में संबंधित संवेदकों और ठेकेदारों पर पेनल्टी लगाने और धारा 91 के तहत रिपोर्ट भिजवाने के लिए निर्देशित भी किया। उन्होंने जिले में सुचारू एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति की समीक्षा करते हुए ट्रांसफार्मर के लोड फिक्सेशन और नए ट्रांसफार्मर लगाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने सीएचसी और पीएचसी में आवश्यक दवाइयों की पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करने, गर्मी से बचाव के लिए आमजन को जागरूक करने तथा फूड इंस्पेक्टरों को औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को बुनियादी सेवाएं और सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी और कार्मिक टीम भावना के साथ कार्य करें।

प्राचीन कुंडों का करें पुनरुद्धार

मुख्यमंत्री ने कहा कि भरतपुर की भौगोलिक स्थिति कटोरे के समान है, इसलिए बरसात के समय जलभराव की समस्या से निपटने के लिए अधिकारी बेहतर प्लानिंग करें। उन्होंने जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि एक विशेष टीम गठित कर शहर की सड़कों पर जलभराव के कारणों का मुआयना करें और स्थायी समाधान निकालें। उन्होंने शहर के प्राचीन कुंडों का पुनरुद्धार और पौधारोपण के संबंध में भी विस्तृत दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिले में एनीकट, नहरों और पोखरों का जीर्णोद्धार करने तथा कच्ची नहरों की सफाई सुनिश्चित की जाए। वहीं, शहर में चल रहे गैस पाइपलाइन कार्य की प्रगति का फीडबैक लेते हुए उन्होंने इसे गति प्रदान करने तथा अन्य निर्माणाधीन कार्यों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री की जन सुनवाई, अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश

मुख्यमंत्री ने भरतपुर सर्किट हाउस में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में आमजन की समस्याएं सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों को प्रभावी समाधान के निर्देश दिए। जन सुनवाई में जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे और विभिन्न जनहित से जुड़े मुद्दे मुख्यमंत्री के समक्ष रखे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जन समस्याओं के निराकरण में पारदर्शिता, संवेदनशीलता एवं जवाबदेही बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी प्रतिबद्धता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है।जन सुनवाई के पश्चात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के अनुरूप मुख्यमंत्री ई-बस से जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में पहुंचे।

समीक्षा बैठक में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, विधायक डॉ. शैलेश सिंह, नौक्षम चौधरी, बहादुर सिंह कोली, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, भरतपुर प्रभारी सचिव आनंदी, संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया, आईजी कैलाश बिश्नोई, भरतपुर जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी, डीग जिला कलेक्टर मयंक मनीष, बीडीए आयुक्त कनिष्क कटारिया, भरतपुर पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा और डीग पुलिस अधीक्षक कांबले शरण गोपीनाथ सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

झुंझुनूं में 8.50 लाख की रिश्वत लेते ग्राम विकास अधिकारी रंगे हाथ गिरफ्तार

हैलो सरकार न्यूज

झुंझुनूं। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी झुंझुनूं इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी राजकुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बेरला, पंचायत समिति सूरजगढ को परिवादी से 8,50,000 रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी झुंझुनूं को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी ने गांव बेरला में स्थित स्वयं की आवासीय भूखण्ड में मेडिकल दुकान का संचालन करता है। परिवादी द्वारा उक्त आवसीय भूखण्ड में स्थित दुकान को व्यवसायिक में परिवर्तित करवाने हेतु ग्राम पंचायत बेरला में आवेदन किया था। राजकुमार ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बेरला द्वारा परिवादी के आवसीय भूखण्ड को व्यवसायिक भूखण्ड में परिवर्तित करने, भूखण्ड की एन.ओ.सी. जारी करने की एवज में दिनांक 19.05.2026 को परिवादी से 8.50 लाख रुपये रिश्वत की मांग की गई। दिनांक 21.05.2026 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन पुनः करवाया गया तो आरोपी राजकुमार ग्राम विकास अधिकारी द्वारा रिश्वत राशि स्वयं को देने के लिए कहा गया। जिस पर ए.सी.बी. के उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ रामेश्वर सिंह, के सुपरवीजन में ए.सी.बी. की झुंझुनूं

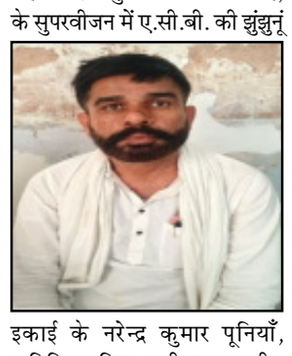

इकाई के नरेन्द्र कुमार पूनियाँ, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय टीम द्वारा रिश्वत मांग के अनुसरण में आज ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया तथा आरोपी राजकुमार ग्राम विकास अधिकारी ने परिवादी को दीपक मेडिकोज सूरजगढ पर बुलाया जहां आरोपी को परिवादी से 8.50 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। रिश्वत राशि 8.50 लाख रुपये आरोपी श्री राजकुमार ग्राम विकास अधिकारी के हाथ से बरामद की गई। मौके पर अग्रीम कार्यवाही जारी है।

ए.सी.बी. की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक एस परिमला के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

श्रीगंगानगर में एसीबी की कार्रवाई-20 हजार रुपये रिश्वत लेते उप निरीक्षक रंगे हाथ गिरफ्तार

हैलो सरकार न्यूज, श्रीगंगानगर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की बीकानेर चौकी ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीगंगानगर जिले के नई मंडी घड़साना पुलिस थाने में तैनात उप निरीक्षक रामेश्वरलाल को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने परिवादी से एक मुकदमे में एफआर (फाइनल रिपोर्ट) लगाने के एवज में इस राशि की मांग की थी। एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि बीकानेर चौकी को इस संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में परिवादी ने बताया कि उसके एक मुकदमे में एफआर लगाने की एवज में उप निरीक्षक रामेश्वरलाल द्वारा 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी। जब परिवादी ने रिश्वत की राशि कम करने का निवेदन किया, तो आरोपी 20,000 रुपये लेने पर सहमत हो गया। शिकायत का सत्यापन करने के बाद, एसीबी उप महानिरीक्षक पुलिस नारायण टोगस के सुपरविजन और बीकानेर चौकी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाकर ट्रेप की कार्रवाई को अंजाम दिया और आरोपी उप निरीक्षक रामेश्वरलाल को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। रिश्वत की पूरी राशि आरोपी के कब्जे से बरामद कर ली गई है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और मौके पर आगे की कार्रवाई जारी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे का अनुसंधान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गंगा माता मंदिर में पूजा

भरतपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत सोमवार को गंगा दशमी के पावन अवसर पर भरतपुर स्थित गंगा माता मंदिर में विधि-

विधान से पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं को गंगाजल, तुलसी के पौधे, श्रीफल एवं प्रसाद वितरित कर भारतीय संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण और आध्यात्मिक चेतना का संदेश दिया। मुख्यमंत्री किला दरवाजे से गंगा माता मंदिर तक पैदल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहर में संचालित विकास कार्यों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मार्ग में आमजन, व्यापारियों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया गया।

कला और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजस्थान की तीन हस्तियां पद्म पुरस्कारों से सम्मानित

हैलो सरकार न्यूज, जयपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार सम्मान समारोह 2026 में देश की नामचीन हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस अवसर पर राजस्थान के तीन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी वर्ष 2026 के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। इनमें लोक कला और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकार एवं समाजसेवी शामिल हैं। कला क्षेत्र में गफरुद्दीन मेवाती जोगी और तगाराम भील को, जबकि समाज सेवा के क्षेत्र में स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया गया। राजस्थान के डीग निवासी गफरुद्दीन मेवाती जोगी को मेवाती लोक संगीत और पारंपरिक लोक विधाओं को संरक्षित एवं विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया। वे पिछले कई दशकों से अधिक समय से भपंग वादन की परंपरा को जीवित रखने में जुटे हुए हैं। उन्हें इस लोक शैली का अनूठा कलाकार माना जाता है। भपंग के साथ-साथ वे अलगोजा, चिकारा और जोगी सारंगी सहित करीब 12 पारंपरिक लोक वाद्य यंत्रों में निपुण हैं। उनकी प्रस्तुतियों में मेवात की लोक संस्कृति और इतिहास की झलक दिखाई देती है। गफरुद्दीन मेवाती जोगी ने लंदन, पेरिस, कनाडा और फ्रांस सहित कई देशों में अपनी प्रस्तुतियां देकर भारतीय लोक संगीत को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है। मेवाती संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके है।

इसी भव्य सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्वारा जैसलमेर निवासी तगाराम भील को भी लोक कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म श्री सम्मान प्रदान किया गया है। भील समुदाय से आने वाले तगाराम भील राजस्थान के प्रसिद्ध अलगोजा वादकों में शामिल हैं। उन्होंने बचपन से ही लोक संगीत को अपनी साधना बना लिया और तीन दशकों से अधिक समय से आदिवासी लोक संगीत परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।

तगाराम भील अलगोजा के साथ-साथ मटका और बांसुरी जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों में भी दक्ष हैं। उन्होंने राजस्थान डेजर्ट फेस्टिवल सहित कई प्रमुख सांस्कृतिक

आयोजनों में प्रस्तुति दी है। उनकी कला को देश विदेश के नामचीन मंचों पर भी सराहा जा चुका है। वे स्वयं अलगोजा वाद्य तैयार करते हैं और उनके बनाए वाद्यों की मांग देश-विदेश तक रहती है। उन्होंने फ्रांस, अमेरिका, जापान, रूस और कई यूरोपीय देशों में अपनी प्रस्तुतियों और कार्यशालाओं के माध्यम से राजस्थान की आदिवासी लोक कला को वैश्विक पहचान दिलाई है।

पद्म सम्मानों की इसी कड़ी में राजस्थान से तीसरी प्रमुख हस्ती श्रीगंगानगर के स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज को समाज सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा पद्म श्री सम्मान से नवाजा गया है। वे लंबे समय से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से समाज कल्याण के कार्यों में सक्रिय हैं। विशेष रूप से दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित बच्चों के लिए उनके योगदान को उल्लेखनीय माना जाता है। स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज ने श्री जगदंबा अंधविद्यालय की स्थापना की थी। यह संस्थान नेत्रहीन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास और देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही यहां मूक-बधिर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय भी संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने श्री जगदंबा धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय की स्थापना कर जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क नेत्र जांच एवं उपचार की व्यवस्था भी शुरू की। पिछले करीब दो दशक से ज्यादा समय से स्वामी ब्रह्मदेव द्वारा स्थापित चिकित्सालय लगातार सेवा कार्यों में जुटा हुआ है। राजस्थान के इन तीनों व्यक्तित्वों को पद्म श्री सम्मान मिलने पर प्रदेशभर में खुशी की लहर है। कला, संस्कृति और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान को देशभर में सराहा जा रहा है।

नरेंद्र मोदी खुद पहले ईंधन के दाम बढ़ने को बताते थे शासन की नाकामी, अब चुप्पी क्यों ?-टीकाराम जूली

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गई बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पांच राज्यों के चुनाव खत्म होते ही देश की जनता पर महंगाई का कहर टूटना शुरू हो गया है। %महंगाई मैन% नरेन्द्र मोदी ने एक बार फिर पेट्रोल के दाम में ?2.82 पैसे और डीजल में ?2.73 पैसे की भारी वृद्धि कर आम जनता की जेब पर सरेआम डाका डाल दिया है। चुनाव के वक्त जनता को गुमराह करने वाली भाजपा का असली लोक-विरोधी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है और अच्छे दिनों का दावा करने वाली सरकार ने जनता को लाचारी के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पुराने बयानों को याद दिलाते हुए उन पर कड़ा तंज कसा। उन्होंने कहा कि आज के प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े आलोचक कोई और नहीं, बल्कि साल 2014 से पहले के खुद %मुख्यमंत्री मोदी% हैं। जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब पेट्रोल और डीजल के दामों में मामूली वृद्धि होने पर भी वे मंचों से बड़े-बड़े राजनीतिक भाषण देते थे। उस वक्त मुख्यमंत्री मोदी कहते थे कि पेट्रोल-डीजल के दामों का बढ़ना दिल्ली सरकार की नाकामी और शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता-जागता सबूत है।

ग्रीष्मकाल में मूक प्राणियों की सुरक्षा के लिए मुख्य सचिव के दिशा-निर्देश

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने ग्रीष्मकाल के दौरान पशु-पक्षियों को तेज गर्मी एवं लू से बचाने तथा उनके लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दोपहर के समय पशुओं का भारवहन तथा कृषि कार्यों के लिए उपयोग पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों, स्थानीय निकायों एवं संबंधित विभागों को इस संबंध में समन्वित रूप से प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक जल स्रोतों के सूखने के कारण पशु-पक्षियों के लिए पेयजल उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण है, ऐसे में सभी संबंधित विभागों एवं आमजन की सहभागिता से इन मूक प्राणियों के लिए गर्मी के मौसम में पेयजल, छाया और चारे की

व्यवस्था के लिए संवेदनशीलता के साथ प्रयास किए जाए। पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण नियमों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश

मुख्य सचिव की ओर से जारी परिपत्र में बताया गया है कि राज्य के अधिकांश भागों में लगातार बढ़ते तापमान एवं तीव्र गर्मी के कारण भारवाहक पशुओं जैसे घोड़े, गधे, खच्चर, बैल एवं भैंसा आदि के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अत्यधिक गर्मी एवं धूप में कार्य कराने से इन पशुओं में हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण, अत्यधिक थकावट तथा मृत्यु जैसी गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। भार ढोने वाले एवं माल ढोने वाले पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण नियम, 1965 के तहत 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक पशुओं से कार्य नहीं लिया जा सकता। इसी प्रकार पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (पशुओं का पैदल परिवहन) नियम, 2001 के अनुसार 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में पशुओं का पैदल परिवहन भी प्रतिबंधित है। जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पुलिस प्रशासन एवं संबंधित विभाग संयुक्त रूप से यह सुनिश्चित करें कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के मध्य पशुओं का भारवहन एवं कृषि कार्यों में उपयोग प्रतिबंधित रहे तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने पशु मालिकों को पशुओं के लिए पर्याप्त छाया, स्वच्छ एवं शीतल पेयजल तथा पौष्टिक चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रति जागरूक करने के निर्देश भी दिए।

राजस्थान में मिलावटखोरों पर सख्ती, नकली घी-तेल का बड़ा भंडाफोड़, 14,000 किलो से ज्यादा माल जब्त

हैलो सरकार न्यूज, जयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जैसलमेर जिले के पोकरण में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली घी और तेल के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान 14 हजार किलो से अधिक मिलावटी घी, पाम ऑयल, सोयाबीन तेल और वनस्पति जब्त की गई, जबकि कुल 13 नमूने जांच के लिए लिए गए हैं।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी शुभमंगला ने बताया कि अतिरिक्त आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) भगवत सिंह के नेतृत्व में जयपुर मुख्यालय की विशेष टीम और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर के सहयोग से यह संयुक्त कार्रवाई की गई।

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पोकरण की लोढ़ा कॉलोनी स्थित

सात्विक ट्रेडिंग कंपनी के मालिक योगेश टावरी के परिसर पर छापा मारा। जांच के दौरान वहां बड़े स्तर पर नकली घी और तेल का निर्माण एवं पैकिंग कार्य संचालित होता मिला। अधिकारियों ने मौके से मिलावटी घी और तेल के पांच नमूने एफएसएसए एक्ट के तहत लिए। साथ ही करीब 10 हजार 260 किलो मिलावटी घी, पाम ऑयल, सोयाबीन तेल और वनस्पति को सीज कर दिया गया।

इसके बाद विभागीय टीम ने सात्विक ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम पर भी कार्रवाई की। यहां विभिन्न ब्रांडों के नाम से नकली घी का भंडारण किया जा रहा था। टीम ने श्री आहार, शुभ, कुबेर, श्रीमूल, विनायक और टॉपर मिल्क फैट सहित अन्य ब्रांडों के आठ नमूने लिए। इसके अलावा करीब 4 हजार किलो मिलावटी घी को भी जब्त किया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर डॉ. राजेंद्र कुमार पालीवाल ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला बड़े स्तर पर खाद्य पदार्थों में मिलावट का प्रतीत होता है। सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद संबंधित आरोपियों के खिलाफ एफएसएसए एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद शर्मा, देवेन्द्र सिंह, लोकेश शर्मा, जगदीश प्रसाद और जैसलमेर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी किशनाराम कड़वासरा भी मौजूद रहे। विभाग का कहना है कि प्रदेशभर में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा ताकि आमजन को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।

प्रतिमा स्थापना को लेकर बवाल, पुलिस पर पथराव के बाद हवाई फायरिंग, भारी पुलिस जाप्ता तैनात

हैलो सरकार न्यूज, दौसा। जिले के लालसोट थाना क्षेत्र के ग्राम लालपुरा (आगला रामा की ढाणी) में खातेदारी भूमि पर डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने के प्रयास को लेकर रविवार देर रात तनावपूर्ण स्थिति बन गई। समझाइश के लिए पहुंची पुलिस टीम पर उग्र भीड़ ने अचानक पथराव कर दिया। घटना में कांस्टेबल लहरीलाल और सतीश सिंह घायल हो गए, जबकि सरकारी वाहन का शीशा टूट गया। हालात बिगड़ने पर पुलिस को आत्मरक्षा में एक राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस जाप्ता तैनात कर दिया गया है। थानाधिकारी पवन कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक समाज विशेष के लोग सीताराम आदि की खातेदारी भूमि पर संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं। मौके पर दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए थे। पुलिस ने समझाइश कर एक पक्ष को वहां से हटा दिया, लेकिन दूसरे पक्ष ने प्रतिमा स्थापना रोकने से नाराज होकर पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया।

पांच जनों को मौके से किया गिरफ्तार

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाथूलाल पुत्र सुवालाल बैरवा, हनुमान पुत्र बजरंग बैरवा, रामस्वरूप पुत्र गंगाधर बैरवा, कमलेश कुमार बैरवा पुत्र मोहनलाल बैरवा और रवि कुमार बैरवा पुत्र गोपाल लाल बैरवा को गिरफ्तार कर लिया। वहीं खेमराज बैरवा, मुकेश, कमलेश पुत्र सुवालाल, बृजेश, दिलखुश पुत्र जगदीश, इन्द्र, रमेश, मुनेश और

दिलखुश पुत्र रमेश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए।

घटना के बाद मंडावरी, रामगढ़ पचवारा और जांमदा थानों के साथ रिजर्व पुलिस लाइन से अतिरिक्त जाब्ता मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने 14 नामजद आरोपियों सहित 50-60 महिला-पुरुषों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।

इधर, खटवा गांव की ढंड की प्रतिमा स्थापना को लेकर बवाल, पुलिस पर पथराव के बाद हवाई फायरिंग, भारी पुलिस जाप्ता तैनढाणी निवासी भगवान सहाय राजेश कुमार शर्मा ने उनकी खातेदारी भूमि में जबरन प्रतिमा स्थापित करने के प्रयास को लेकर 22 जनों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है।

मौके पर पहुंचे एसडीएम व राजस्व टीम

मामले की सूचना पर एसडीएम और राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। राजस्व टीम ने जांच में भूमि को रामजीलाल, सीताराम शर्मा आदि की निजी खातेदारी भूमि बताया। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर प्रतिमा को कब्जे में लेकर थाने में सुरक्षित रखवा दिया है। इलाके में स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है।

भारत की कृषि आत्मा को समर्पित जनसेवा प्रसारक का स्वर्णिम अध्याय

(लेखक - विनोद कुमार सिंह 'तकियावाला')

डीडी किसान - 11 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा, जिसने खेत-खलिहानों को दिया ज्ञान, विश्वास और नई दिशा

भारत केवल शहरों और महानगरों का देश नहीं है।इसकी वास्तविक आत्मा गांवों में बसती है,जहाँ खेतों की हरियाली,किसान का श्रम और ग्रामीण संस्कृति मिलकर राष्ट्र की आर्थिक शक्ति को मजबूत बनाते हैं।भारतीय लोकतंत्र की जड़ें यदि गाँवों में हैं,तो गाँवों की धड़कन किसान है।यही कारण है कि खेती, किसान और ग्रामीण भारत से जुड़ी सूचना,शिक्षा और जागरूकता का महत्व अत्यंत बढ़ जाता है।इसी आवश्यकता को समझते हुए 26 मई 2015को भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने फडीडी किसानफ चैनल की शुरुआत की थी।आज यह चैनल अपनी सफलतापूर्वक 11 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पूरी कर चुका है। यह केवल एक टेलीविजन चैनल नहीं,बल्कि भारतीय कृषि समाज की आवाज,किसानों का साथी और ग्रामीण भारत का विकास मंच बन चुका है।डीडी किसान की शुरुआत ऐसे समय हुई थी जब भारतीय कृषि अनेक चुनौतियों से जूझ रही थी।जलवायु परिवर्तन, अनिश्चित मानसून,खेती की बढ़ती लागत, घटती कृषि योग्य भूमि,बाजार की अस्थिरता और वैज्ञानिक जानकारी के अभाव जैसी समस्याएँ किसानों को प्रभावित कर रही थीं।ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल जागरूकता सीमित थी और अधिकांश किसान परंपरागत अनुभवों के आधार पर खेती कर रहे थे।ऐसे समय में किसानों के लिए समर्पित 24म7 चैनल की शुरुआत अपने आप में ऐतिहासिक कदम था।इस चैनल का उद्देश्य केवल कृषि समाचार देना नहीं था,बल्कि फकिसान को सूचना से सशक्तफ बनाना था।यही कारण है कि डीडी किसान ने खेती को परंपरागत सीमाओं से निकाल कर आधुनिक विज्ञान,तकनीक और बाजार व्यवस्था से जोड़ने का कार्य किया।भारत दुनिया की सबसे बड़ी कृषि अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। देश की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है।ऐसे विशाल कृषि समाज के लिए समर्पित राष्ट्रीय चैनल की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी।डीडी किसान ने इस आवश्यकता को पूरा करते हुए किसानों तक उपयोगी और वैज्ञानिक जानकारी पहुँचाने का सशक्त माध्यम तैयार किया।डीडी किसान की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसने किसानों को फसूचना का अधिकारफ व्यवहारिक रूप में प्रदान किया। वर्षों तक किसान केवल स्थानीय अनुभवों और सीमित जानकारी पर निर्भर रहते थे,लेकिन इस चैनल ने खेती को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की नई सोच विकसित की। मौसम आधारित खेती,जल संरक्षण,ड्रिप इरिगेशन,प्राकृतिक खेती, जैविक उर्वरकों का उपयोग, फसल विविधीकरण, मधुमक्खी पालन,मत्स्य पालन,डेयरी उद्योग और कृषि आधारित स्वरोजगार जैसे विषयों को लगातार प्रमुखता दी गई।चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम फमौसम खबरफऔरफमंडी समाचारफ किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए।फमौसम खबरफ में विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के अनुसार मौसम पूर्वानुमान और फसल आधारित सलाह दी जाती रही, जबकि फमंडी समाचारफ ने किसानों को विभिन्न मंडियों के भाव और बाजार की जानकारी देकर बेहतर निर्णय लेने में सहायता प्रदान की।डीडी किसान ने किसानों को खेती की बदलती तकनीकों से भी जोड़ा। आज देश का किसान मोबाइल एप, ड्रोन तकनीक,मिट्टी परीक्षण, माइक्रो इरिगेशन,डिजिटल मंडी और प्राकृतिक खेती जैसे आधुनिक कृषि शब्दों से परिचित है।इस जागरूकता के पीछे जनसंचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है,जिसमें डीडी किसान अग्रणी रहा।चैनल ने केवल खेती तक अपने कार्यक्रम सीमित नहीं रखे, बल्कि ग्रामीण जीवन के व्यापक विकास को भी केंद्र में रखा।महिला स्वयं सहायता समूह,ग्रामीण उद्यमिता,डिजिटल भुगतान,कौशल विकास,ग्रामीण स्वास्थ्य,शिक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी जैसे विषयों को भी प्रमुखता दी गई।यही कारण है कि यह चैनल फकृषि चैनलफ से आगे बढ़कर फग्रामीण भारत का विकास चैनलफ बन गया।डीडी किसान की एक प्रेरक पहल फसफल किसानफ कार्यक्रम रहा। इसमें देशभर के उन किसानों की कहानियाँ दिखाई गईं जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद आधुनिक तकनीक अपनाकर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की।किसी किसान ने जैविक खेती से लाखों की आय अर्जित की, तो किसी ने मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन को रोजगार का माध्यम बनाया।इन वास्तविक कहानियों ने लाखों किसानों के भीतर आत्मविश्वास जगाया।भारत में दूरदर्शन की परंपरा स्वयं अत्यंत गौरवशाली रही है।वर्ष 1967 में शुरू हुआ फकृषि दर्शनफ कार्यक्रम भारतीय टेलीविजन इतिहास के सबसे लंबे समय तक चलने वाले कार्यक्रमों में गिना जाता है।डीडी किसान ने उसी परंपरा को आधुनिक स्वरूप और 24 घंटे की निरंतरता प्रदान की।डीडी किसान की एक बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसने कृषि वैज्ञानिकों,शोध संस्थानों और किसानों के बीच सीधा संवाद स्थापित किया।कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों से जुड़े विशेषज्ञों को मंच देकर चैनल ने वैज्ञानिक शोध को खेतों तक पहुँचाने का कार्य किया।इससे फलैब टू लैंडफ की अवधारणा को मजबूती मिली।आज डिजिटल मीडिया के युग में भी डीडी किसान का महत्व कम नहीं हुआ है।देश के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी दूरदर्शन और डीडी फ्री डिश की पहुँच अत्यंत व्यापक है।सीमित संसाधनों वाले किसान परिवारों तक निःशुल्क पहुँचने की क्षमता ने इस चैनल को विशेष रूप से प्रभावशाली बनाया है।यही इसकी सबसे बड़ी सामाजिक शक्ति है।ग्रामीण भारत में आज भी ऐसे लाखों परिवार हैं जहाँ निजी डिजिटल प्लेटफॉर्म या महँगे चैनल उपलब्ध नहीं हैं,लेकिन डीडी किसान उनके घर तक पहुँचता है।यही कारण है कि इसकी विश्वसनीयता लगातार बनी हुई है।डीडी किसान ने प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को लोकप्रिय बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।पिछले कुछ वर्षों में रसायन मुक्त खेती,देसी बीजों के संरक्षण और मोटे अनाज यानी मिलेट्स के प्रति बढ़ती जागरूकता में जनसंचार माध्यमों की बड़ी भूमिका रही है।चैनल ने लगातार मिलेट्स, गो आधारित खेती और पर्यावरण संतुलन जैसे विषयों को प्रसारित कर कृषि को सतत विकास से जोड़ने का प्रयास किया।जल संकट और बदलते जलवायु परिदृश्य को देखते हुए चैनल ने फपर ड्रॉप मोर क्रॉपफ,सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचयन जैसी तकनीकों को भी प्रमुखता दी।खेती में पानी बचाने की तकनीकों पर आधारित कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में काफी लोकप्रिय हुए।डीडी किसान ने ग्रामीण महिलाओं की भूमिका को भी नई पहचान दी।खेतों से लेकर पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है।चैनल ने महिला किसानों और स्वयं सहायता समूहों की सफलता की कहानियों को सामने लाकर उन्हें प्रेरणा का स्रोत बनाया। वैश्विक महामारी कोविड-19 महामारी के दौरान डीडी किसान किसानों के लिए भरोसेमंद सूचना माध्यम बनकर उभरा। लॉकडाउन के समय किसानों के सामने फसल कटाई,श्रमिक संकट और परिवहन जैसी समस्याएँ थीं।उस समय चैनल ने किसानों तक आवश्यक जानकारी पहुँचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया।उस दौर में यह चैनल ग्रामीण भारत की सूचना जीवनरेखा बन गया था।तकनीकी दृष्टि से भी डीडी किसान ने समय के साथ स्वयं को बदला है।हाल के वर्षों में चैनल ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और आधुनिक प्रस्तुति शैली को अपनाया।आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एआई एंकर फएआई कृषफ और फएआई भूमिफ की शुरुआत ने इसे तकनीकी नवाचार की दिशा में भी अग्रणी बना दिया।यह इस बात का संकेत है कि भारतीय कृषि संचार भी तेजी से डिजिटल भविष्य की ओर बढ़ रहा है।डीडी किसान की 11 वर्षों की यात्रा वास्तव में भारतीय कृषि संचार क्रांति की कहानी है।यह यात्रा केवल एक चैनल की सफलता नहीं, बल्कि उस सोच की सफलता है जिसमें किसान को राष्ट्र निर्माण का केंद्र माना गया।आज भारत फविकसित भारत 2047फ के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है।ऐसे समय में कृषि क्षेत्र की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला किसान ही हैं।इसलिए किसानों को सशक्त बनाना केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दायित्व भी है।डीडी किसान ने इन 11 वर्षों में यह सिद्ध किया है कि यदि सही जानकारी सही समय पर किसानों तक पहुँचे,तो खेती केवल जीविका का साधन नहीं,बल्कि सम्मान और समृद्धि का मार्ग भी बन सकती है। खेतों से लेकर शोध प्रयोगशालाओं तक,गाँवों से लेकर नीति निर्माण तक,इस चैनल ने संवाद का ऐसा पुल तैयार किया है जिसने भारतीय कृषि समाज को नई दिशा दी है।यह भी उल्लेखनीय है कि जिस समय निजी चैनल मनोरंजन आधारित कार्यक्रमों की दौड़ में लगे हुए थे,उसी समय डीडी किसान देश के उस वर्ग को केंद्र में रख रहा था जो वास्तव में भारत की अर्थ व्यवस्था की रीढ़ है।यह भारतीय सार्वजनिक प्रसारण व्यवस्था की सामाजिक जिम्मेदारी और जनसेवा की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है।आने वाले समय में आवश्यकता इस बात की है कि डीडी किसान को और अधिक तकनीकी संसाधन,क्षेत्रीय भाषाई विस्तार और डिजिटल पहुँच प्रदान की जाए ताकि यह देश के हर किसान तक और अधिक प्रभावी ढंग से पहुँच सके।अलग-अलग राज्यों की कृषि परिस्थितियों के अनुसार स्थानीय भाषाओं में कार्यक्रमों का विस्तार भविष्य की बड़ी आवश्यकता होगी।कृषि केवल अन्न उत्पादन का माध्यम नहीं है।यह भारत की संस्कृति, सभ्यता और आत्मनिर्भरता का आधार है।खेतों की मिट्टी में केवल अन्न नहीं उगता,बल्कि देश का भविष्य भी आकार लेता है।डीडी किसान की 11 वर्षों की यह गौरवशाली यात्रा वास्तव में भारतीय किसान के संघर्ष,श्रम और आत्मविश्वास को समर्पित यात्रा है। यह चैनल आने वाले वर्षों में भी किसानों के जीवन में नई उम्मीद, नई जानकारी और नई ऊर्जा का संचार करता रहेगा।अंततः कहा जा सकता है कि भारतीय जनसंचार के इतिहास में डीडी किसान ने जो भूमिका निभाई है,वह केवल प्रसारण तक सीमित नहीं है।यह ग्रामीण भारत के उत्थान,कृषि चेतना और आत्म निर्भर भारत के निर्माण की एक जीवंत गाथा बन चुका है।सच मायनों में डीडी किसान आज भारत की मिट्टी की आवाज बन गया है-ऐसी आवाज, जो खेतों से उठती है,किसानों के सपनों से जुड़ती है और राष्ट्र के भविष्य को मजबूत बनाती है।

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संपादकीय

रुपये की गिरावट

यूं देश के आयात-निर्यात असंतुलन के चलते पिछले दो दशकों से रुपये के मूल्य में लगातार गिरावट देखी गई है, लेकिन हाल के कुछ महीनों में इस गिरावट में तेजी आई है। खासकर ईरान-अमेरिकी युद्ध शुरू होने के बाद इसमें छह फीसदी की चिंताजनक गिरावट आई है। जो हमारी आयात पर अत्यधिक निर्भरता को ही दर्शाता है। यद्यपि दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए ऐसे मुद्रा संकट कोई नई बात नहीं है, लेकिन हालिया गिरावट हमारी चिंता बढ़ाने वाली है। दरअसल, यह गिरावट भू-राजनीतिक अस्थिरता, कच्चे तेल की कीमतों में अप्रत्याशित तेजी, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अनिश्चितता से मुद्रास्फीति और धीमी वैश्विक आर्थिक वृद्धि के बीच हो रही है। इन दबावों ने मिलकर एक ऐसा संवेदनशील वातावरण बनाया है, जिसमें रुपये की कमजोरी व्यापक आर्थिक व्यवधानों को जन्म दे रही है। वैसे तो बढ़ता आयात असंतुलन ही रुपये की गिरावट के मूल में है। सबसे बड़ा संकट तो कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता का है, जो करीब 88 फीसदी है। इसके अलावा खाद्य तेल, उर्वरक आदि आवश्यक वस्तुओं का आयात लगातार बढ़ा है। वहीं रुपये के डॉलर के मुकाबले लगातार गिरने से ये वस्तुएं महंगी हो गई हैं। खासकर ईंधन की बढ़ती कीमतों का असर परिवहन, मालभाड़ा वृद्धि, भोजन और घरेलू खर्चों पर पड़ा है। इसके चलते रुपये के अवमूल्यन से कंपनियां तथा देश के नीति-निर्माता भी खासे चिंतित हैं। विदेशी मुद्रा में ऋण लेने वाली भारतीय कंपनियों पर ऋण चुकाने का अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है। दरअसल, इन सभी कारणों से बढ़ते व्यापार घाटे का चालू खाते के घाटे पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। जिसके चलते शेयर बाजार में लगातार गिरावट का ट्रेंड देखा जा रहा है। वास्तव में विदेशी निवेशक अनिश्चितता के वातावरण में सुरक्षित अमेरिकी कंपनियों में निवेश बढ़ा रहे हैं। फलत- अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश में लगातार निकासी का रुझान देखा जा रहा है। जिसने हमारी आर्थिक चिंताओं को और बढ़ाया है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस जारी अस्थिरता को कम करने के लिये विदेशी मुद्रा भंडार के माध्यम से हस्तक्षेप किया है, लेकिन ऐसे उपाय महज गिरावट की गति को कम करने के अलावा बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर, सोलहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने तर्क दिया है कि रुपये का स्वाभाविक रूप से अवमूल्यन करने से समय के साथ व्यापार असंतुलन को दुरुस्त करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने केंद्रीय बैंक से आग्रह किया है कि वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान के कारण होने वाले मुद्रा के उतार-चढ़ाव से निपटने के लिये विशिष्ट विनिमय दर लक्ष्यों मसलन सौ रुपये प्रति डॉलर से आगे बढ़कर विचार करना चाहिए। हालांकि, अनियंत्रित अवमूल्यन से गंभीर जोखिम भी पैदा हो सकते हैं। देश के नीति-निर्माताओं को बाजार समायोजन की अनुमति देने और अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के बीच सावधानी से संतुलन बनाने की जरूरत होगी। निश्चित रूप से सरकार की ओर से मुद्रास्फीति का कुशल प्रबंधन और अर्थव्यवस्था में निवेशकों का भरोसा बनाये रखना, देश की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में मददगार साबित हो सकता है।

पेट्रोल मूल्य वृद्धि का विरोधाभास, ईंधन बना मुनाफे का इंजन

(लेखक-भूपेन्द्र गुप्ता)

भारत में पेट्रोल की बढ़ती कीमतें अब केवल अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कहानी नहीं रह गई हैं। वे सरकारों की उस आर्थिक संरचना का प्रतीक बन चुकी हैं जिसमें ईंधन उपभोक्ता की आवश्यकता कम और राजस्व का सबसे भरोसेमंद स्रोत अधिक दिखाई देता है। आज जब ईरान युद्ध और पश्चिम एशिया के तनाव के कारण पेट्रोल की कीमतें फिर बढ़ रही हैं, तब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में जनता केवल वैश्विक संकट का बोझ उठा रही है, या फिर उस कर-व्यवस्था का भी भार झेल रही है जिसने ईंधन को 'राजस्व मशीन' बना दिया है?

भारत जैसे देश में, जहाँ करोड़ों लोग प्रत्यक्ष कर दायरे में नहीं आते, पेट्रोल-डीजल पर लगाया गया टैक्स सरकारों के लिए सबसे आसान आय का साधन बन गया है। उपभोक्ता हर दिन, हर लीटर के साथ टैक्स देता है—बिना किसी बहस, नोटिस या प्रतिरोध के। यही कारण है कि पेट्रोल की कीमत अब केवल ऊर्जा लागत से तय नहीं होती; उसमें सरकारों की राजकोषीय भूख भी शामिल होती है।

वर्तमान मूल्य वृद्धि इसी विरोधाभास को उजागर करती है। सरकारें कह रही हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महँगा हो गया है, इसलिए कीमतें बढ़ना स्वाभाविक है। यह तर्क आंशिक रूप से ही सही है।

भारत लगभग 85 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए वैश्विक संकटों का असर यहाँ पड़ना तय है। लेकिन सवाल यह है कि जब कच्चा तेल सस्ता हुआ था तब जनता को उसी अनुपात में राहत क्यों नहीं मिली?

कोविड काल और उसके बाद कई महीनों तक अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें ऐतिहासिक रूप से नीचे चली गई थीं। उस समय जनता को उम्मीद थी कि पेट्रोल-डीजल सस्ते होंगे। लेकिन हुआ उल्टा। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, और राज्यों ने वैट(मूल्य वर्धित टैक्स) बनाए रखा और पेट्रोल के दाम ऊँचे ही बने रहे। सरकारों का राजस्व बढ़ता गया, जबकि उपभोक्ता राहत की प्रतीक्षा करता रहा।

यहीं से 'ऊर्जा लागत मॉडल' और 'राजस्व मॉडल' का अंतर स्पष्ट होता है।

ऊर्जा लागत मॉडल कहता है कि ईंधन की कीमत मुख्यतः तेल की वास्तविक लागत से तय होनी चाहिए। लेकिन राजस्व मॉडल में ईंधन सरकार के बजट संतुलन का उपकरण बन जाता है। भारत में धीरे-धीरे यही हुआ है।

आज भी पेट्रोल की कीमत का बड़ा हिस्सा टैक्स है। यदि पेट्रोल का वास्तविक बेस प्राइस लगभग ₹55-60 प्रति लीटर है, तो उपभोक्ता पंप पर '110 के आसपास भुगतान करता है। यानी वह केवल पेट्रोल नहीं खरीद रहा है, बल्कि भारी कर-व्यवस्था का वित्तपोषण भी खरीद रहा है।

सबसे बड़ा विरोधाभास तब दिखाई देता है जब सरकारें एक ओर जनता से 'खर्च कम करने', 'सादगी अपनाने' और 'वैश्विक संकट सहने' की अपील करती हैं, वहीं दूसरी ओर पेट्रोल-डीजल को राजस्व संग्रह के स्थायी साधन की तरह इस्तेमाल करती रहती हैं। यदि वास्तव में संकट साझा है, तो उसका बोझ केवल उपभोक्ता पर क्यों डाला जाए? टैक्स संरचना में स्वतः कमी क्यों नहीं आती?

यह भी ध्यान देने योग्य है कि पेट्रोल-डीजल पर टैक्स एक प्रतिगामी कर (रिग्रेसिव टैक्स) की तरह काम करता है। अमीर और गरीब—दोनों एक लीटर पेट्रोल पर लगभग समान टैक्स देते हैं। लेकिन उसका वास्तविक बोझ गरीब और मध्यवर्ग पर अधिक पड़ता है। डीजल महँगा होते ही परिवहन महँगा होता है, और फिर खाद्यान्न से लेकर निर्माण सामग्री तक सबकी कीमतें बढ़ जाती हैं। यानी ईंधन मूल्य वृद्धि केवल वाहन चलाने वालों की समस्या

नहीं रहती , वह पूरी अर्थव्यवस्था में महँगाई का दबाव पैदा करती है।

सरकारों का तर्क है कि इसी राजस्व से सड़कें बनती हैं, कल्याणकारी योजनाएँ चलती हैं और राजकोषीय घाटा नियंत्रित होता है। यह तर्क पूरी तरह गलत नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या जनता को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार राहत दे, तब उसका लाभ सीधे उपभोक्ता तक पहुँचे? और यदि संकट के समय जनता से त्याग अपेक्षित है, तो क्या सरकारों को भी अपने कर ढाँचे में लचीलापन नहीं दिखाना चाहिए?

वर्तमान पेट्रोल मूल्य वृद्धि केवल एक आर्थिक घटना नहीं है; यह उस नीति-दर्शन का प्रतिबिंब है जिसमें ईंधन को जीवन की आवश्यकता कम और राजस्व के अवसर के रूप में अधिक देखा जाने लगा है। जब तक पेट्रोल-डीजल को स्थायी कर-स्रोत की तरह इस्तेमाल किया जाता रहेगा, तब तक हर वैश्विक संकट का पहला और सबसे भारी असर आम भारतीय नागरिक की जेब पर ही पड़ेगा।

(लेखक स्वतंत्र विश्लेषक हैं)

चिंतन मनन

सादगी और निष्ठा

मोतीहारी में गांधीजी कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहे थे- आज अवंतिका आने वाली होगी, उसे स्टेशन से लिवा लाना और कमरे में ठहरा देना। एक ने कहा-बापू उसे इन साधारण कमरों में चटाई पर सोना क्यों पसंद होगा? वह तो पहले दरजे में सफर की आदी है। बापू ने कहा-वह जनसेवक के तौर पर आ रही है। जनसेवक के अनुरूप अगर तीसरे दरजे में आई तो उसे यहीं रखूंगा, वरना वापस भेज दूंगा। पर बापू .... दूसरे ने संकोच में कहा-उनके पास पैसा है, वह भी उन्हीं का कमाया हुआ।

उसे खर्च करने में क्या बुराई है? खर्च का मतलब अपव्यय तो नहीं। स्वयं सेवक गांधीजी के सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी के साथ आवंतिका बाई को लेने स्टेशन गए। देवदास ही अकेले उन्हें पहचानते थे। देवदास ने उम्मीद के मुताबिक उन्हें दूसरे दरजे के डिब्बों में खोजा, लेकिन कहीं पता न चला। तब वे निराश होकर वापस आ गए और खबर दी कि अवंतिका बाई इस गाड़ी से नहीं आईं। यह सुनकर सब लोग हंसने लगे। दरअसल अवंतिका अपने पति के साथ पहले ही एक साधारण कमरे में ठहर चुकी थीं। यात्रा उन्होंने तीसरे दर्जे में की थी और बापू की कसौटी पर खुद को खरा साबित किया।

शाम को गांधीजी उन्हें समझाने लगे- किस तरह बड़हखा गांव जाकर काम शुरू करना करना है। इस पर कस्तूरबा ने कहा- ये आज ही आए हैं और कल दीवाली है। दीवाली मनाकर जाएं। नहीं ऐसा नहीं होगा, इन्हें कल सुबह ही निकलना होगा। गांधीजी का स्वर तेज था। एक दिन में क्या हो जाएगा? जनसेवक को निठल्ले नहीं बैठना है। तभी अवंतिका बोलीं- बापू, आप मुझे यह बताएं कि बड़हखा के कायाकल्प के लिए मुझे क्या करना है। गांव की समस्याओं का तो वहीं जाकर अध्ययन करना होगा और गांव वालों का विश्वास जीतना होगा। और विश्वास जीतने के लिए क्या करना होगा? सादगी और निष्ठा का पालन ही तुम्हें विश्वस्त बनाएगा। जनसेवक की यही संपत्ति है। यह सुनकर आवंतिका बाई तैयारी में जुट गईं।

विचार मंथन

घटता विदेशी मुद्रा भंडार, भारतीय अर्थव्यवस्था पर बढ़ता संकट

(लेखक-सनत जैन)

भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से 'विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था' का प्रचार किया गया, उसके पीछे की वास्तविकता अब धीरे-धीरे सामने आने लगी है। शेयर बाजार को रिकॉर्ड स्तर पर, विदेशी निवेश और बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार को आर्थिक मजबूती का प्रतीक बताया गया था। अब वही संकेतक गंभीर संकट की ओर इशारा कर रहे हैं।

पिछले दस वर्षों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने भारतीय शेयर बाजार में भारी निवेश किया, यह निवेश दीर्घकालिक औद्योगिक विकास की बजाय अल्पकालिक मुनाफाखोरी पर आधारित रहा। जब-जब वैश्विक परिस्थितियां अनुकूल रहीं, विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से बड़ा लाभ कमाया। भारतीय शेयर बाजार का अपयोग सट्टा बजार के रुप में करके विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से भारी कमाई की है। शेयर बाजार में संकट आते ही भारी निकासी शुरू कर दी। पिछले दो वर्षों में ही लगभग 78 बिलियन डॉलर की निकासी यह साबित करती है, विदेशी निवेशक पूंजी भारत को स्थायी विकास में साझेदार नहीं, बल्कि लाभ कमाने का बाजार मानकर कमाई कर भारतीय पूंजी को विदेश तो जा रही थी। इसके विपरीत भारतीय संस्थागत निवेशकों—बैंक, बीमा कंपनियां और म्यूचुअल फंड—ने बाजार को संभालने के लिए लगातार शेयर बाजार में निवेश किया। इसका अर्थ यह है कि शेयर बाजार की वास्तविक मजबूती घरेलू निवेश पर टिकी हुई है। जबकि विदेशी निवेशकों ने निवेश निकालकर अस्थिरता को बढ़ाने का काम किया है।

स्थिति की गंभीरता केवल शेयर बाजार तक सीमित नहीं है। भारत का आयात, लगातार निर्यात से अधिक कई वर्षों से बना हुआ है। कच्चे तेल, गैस और उर्वरक जैसे आवश्यक उत्पादों के लिए भारत को भारी मात्रा में डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय तनाव, विशेषकर पश्चिम एशिया के संकट और अमेरिका-ईरान टकराव ने ऊर्जा कीमतों को बढ़ाया है। दूसरी ओर डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। यदि रुपया 100 प्रति डॉलर के स्तर तक पहुंचता है, तो आयातित महंगाई और भी भयावह हो जाएगी।

चिंता का सबसे बड़ा विषय विदेशी मुद्रा भंडार है। जिस विदेशी मुद्रा भंडार को सरकार आर्थिक सुरक्षा कवच बताती रही है। उसकी वास्तविक स्थिति अब भारी दबाव में दिखाई दे रही है। रिजर्व बैंक रुपए को संभालने के लिए बाजार में डॉलर बेच रहा है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ रहा है। यदि यही स्थिति जारी रही, तो भारत को भुगतान संतुलन संकट का सामना करना पड़ सकता है। 1991 के आर्थिक संकट की यादें फिर ताजा होने लगी हैं। उस समय भी आयात भुगतान और विदेशी मुद्रा की कमी सबसे बड़ी समस्या बनी थी।

एक अन्य गंभीर पहलू भारतीय पूंजी का विदेशों की ओर पलायन है। पिछले वर्षों में अनेक उद्योगपतियों और अरबपतियों ने विदेशों में निवेश बढ़ाया है। लाखों भारतीय नागरिकों ने विदेशी नागरिकता तक ली है। इससे यह संकेत मिलता है, देश का बड़ा पूंजी वर्ग भारतीय अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक स्थिरता को लेकर स्वयं आश्वस्त नहीं है। ऐसे समय में जब देश के भीतर निवेश और रोजगार सृजन की आवश्यकता है, तब बड़े औद्योगिक समूहों द्वारा अमेरिका एवं अन्य देशों में अरबों डॉलर का निवेश करना भारतीय अर्थ-व्यवस्था को लेकर कई प्रश्न खड़े करता है।

सरकार की गलत आर्थिक नीति आलोचना के घेरे में आ गई है। केंद्र और राज्य सरकारों पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है। राजकोषीय घाटा नियंत्रण से बाहर जाता दिखाई दे रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से लगातार भारी लाभांश लेना और बैंकों पर निर्भरता बढ़ाना, यह दर्शाता है, सरकार के पास संसाधनों का संकट गहराता जा रहा है।

यह आशंका व्यक्त की जाने लगी है भारत 'लेहमन ब्रदर्स' जैसी स्थिति में पहुंच सकता है। भारतीय वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के आर्थिक संकेतकों में बढ़ती अस्थिरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी विशाल घरेलू बाजार, सेवा क्षेत्र और कृषि उत्पादन पर टिकी हुई है। यदि आयात पर नियंत्रण, पूंजी पलायन, बढ़ता कर्ज और कमजोर होती मुद्रा पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया, तो आर्थिक मंदी और महंगाई का दोहरा संकट भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरा सकता है।

सरकार को उत्पादन, निर्यात, रोजगार और घरेलू निवेश को मजबूत करने वाली ठोस आर्थिक नीतियों पर काम करना होगा। पूंजीपतियों के हित में निर्णय के स्थान पर कठोर वित्तीय नियंत्रण की नीतियाँ तुरन्त लागू करनी होंगी। अन्यथा विदेशी पूंजी पर अत्यधिक निर्भरता भारत को भविष्य में गंभीर आर्थिक अस्थिरता की ओर धकेल सकती है। अर्थशास्त्री चिंतित हैं। 1991 और 2008 की लेहमेन ब्रदर्श जैसे खतरें की आहट मिनले लगी है। समय रहते कठोर निर्णय लेने की जरुरत है।

अनिल अंबानी की रिलायंस पावर मुनाफे से घाटे में आई, लुढ़कर कर आधे हुए शेयर

नई दिल्ली।

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर मुनाफे से घाटे में आ गई है। अनिल अंबानी की पावर कंपनी को 31 मार्च 2026 को खत्म हुई चौथी तिमाही में 494 करोड़ रुपए का कंसॉलिडेटेड घाटा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में रिलायंस पावर को 125.57 करोड़ रुपए का कंसॉलिडेटेड मुनाफा हुआ था। रिलायंस पावर के शेयर सोमवार को बीएसई में गिरावट के साथ 26.67 रुपए पर कारोबार कर रहे थे। रिलायंस पावर के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से आधे से ज्यादा लुढ़क गए हैं। रिलायंस पावर के शेयर 11 जून 2025 को 76.49 रुपए पर थे। कंपनी के शेयर 25 मई को 26.67 रुपए पर जा पहुंचे हैं। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में 9 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, पिछले 6 महीने में रिलायंस पावर के शेयर 28 फीसदी से ज्यादा टूट गए हैं। इस साल अब तक रिलायंस पावर के शेयरों में 23 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। रिलायंस पावर के शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 95 फीसदी से ज्यादा लुढ़क गए हैं। रिलायंस पावर के शेयरों का ऑल टाइम हाई लेवल 565.65 रुपए है। कंपनी के शेयर 11 फरवरी 2008 को इस स्तर पर थे। इस लेवल से रिलायंस पावर के शेयर 95 फीसदी से ज्यादा टूट गए हैं। रिलायंस पावर ने मई 2008 में अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दिया है। कंपनी ने 3:5 के रेशियो में अपने निवेशकों को बोनस शेयर दिए यानी, कंपनी ने हर 5 शेयर पर अपने शेयरधारकों को 3 बोनस शेयर बांटे। रिलायंस पावर की टोटल इनकम चौथी तिमाही में घटकर 1946.33 करोड़ रुपए रही। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी की टोटल इनकम 2065.64 करोड़ रुपए रही है। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी को 336.89 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। वहीं, इससे पहले वित्त वर्ष 2024-25 में रिलायंस पावर को 2947.83 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी की टोटल इनकम घटकर 7988.52 करोड़ रुपए रही है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 8257.04 करोड़ रुपए थी।

ग्रामीण रोजगार के नए युग की शुरुआत, वीबी-जी-राम जी के मसौदा नियम जारी

1 जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह लेगा यह अधिनियम

मुंबई ।

केंद्र सरकार ने विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम 2025 (वीबी-जी-राम जी) के मसौदा नियम सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी कर दिए। यह नया अधिनियम 1 जुलाई 2026 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का स्थान लेगा और ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए एक नए आवंटन मॉडल का प्रस्ताव करता है। मसौदा नियमों पर 21 जून 2026 तक टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। वीबी-जी-राम जी के मसौदा नियमों के अनुसार, केंद्र एक वित्त वर्ष में राज्यों को मानक निधि आवंटन के लिए 16वें वित्त आयोग के क्षैतिज हस्तांतरण फॉर्मूले का उपयोग करेगा। वित्त वर्ष 2027 से शुरू होकर, इस मानदंड-आधारित आवंटन का एक हिस्सा राज्यों के प्रदर्शन से भी जुड़ा होगा, जिसमें समय पर मजदूरी भुगतान, सामाजिक ऑडिट का अनुपालन और कार्यों को पूरा करने का प्रतिशत जैसे कारक शामिल होंगे। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवंटन प्रदर्शन या अन्य उपयुक्त मानदंडों पर आधारित होगा। अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच कोष का साझाकरण 60:40 होगा, जबकि उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 रहेगा। हालांकि, सिविल सोसायटी के एक समूह ने इस नए मानक आवंटन की आलोचना की है।

उनका तर्क है कि यह केंद्र को राज्यों को आवंटित की जाने वाली धनराशि की मात्रा मनमाने ढंग से तय करने का अधिकार देता है, जिससे रोजगार के दिनों की संख्या प्रभावित होगी और यह मनरेगा की मांग-आधारित भावना के विरुद्ध है। इसके जवाब में केंद्र ने स्पष्ट किया है कि मानदंड-आधारित धन मुहैया कराना वीबी-जी-राम जी को भारत सरकार की अधिकांश योजनाओं के बजट मॉडल के अनुरूप बनाता है और इससे रोजगार गारंटी कम नहीं होगी।

शेयर बाजार भारी तेजी के साथ बंद

सेंसेक्स 1,134 , निफ्टी 330 अंक उछला

मुम्बई ।

घरेलू शेयर बाजार सोमवार को सप्ताह के पहले ही कारोबारी दिन भारी तेजी के साथ बंद हुआ। ये उछाल दुनिया भर के बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही खरीददारी हावी रहने से आया है। अमेरिका-ईरान के बीच समझौते की बढ़ती उम्मीदों से भी निवेशकों में उत्साह आया है। इसी कारण दिन भर के बाजारों के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 1,134 अंक बढ़कर 76,549.82 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 330 अंक की ऊपर आकर 24,049.55 के पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान हर क्षेत्र में तेजी रही। ऑयल एंड गैस, मीडिया, ऑटो, बैंकिंग, एनर्जी और रिएल्टी सेक्टर्स में 1-1 फीसदी से ज्यादा की मजबूती रही। वहीं मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी बढ़त रही। बड़े शेयरों के साथ-साथ छोटे और मध्यम शेयरों में भी आज काफी खरीदारी रहीं। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 0.8 फीसदी की बढ़त रही जबकि स्मॉलकैप इंडेक्स भी 1 फीसदी उछला।

आज अदाणी समूह की अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयरों में उछाल आया। एक रिपोर्ट के बाद कंपनी के शेयरों में निवेशकों ने जमकर खरीदारी की, जिससे यह स्टॉक 12 फीसदी से ज्यादा उछलकर 2,850.80 के साथ अपने 52 हफ्ते के नए उच्च स्तर पर पहुंच गये।

बाजार में कुछ शेयरों में मुनाफावसूली दर्ज की गयी। इसमें मैक्स हेल्थकेयर , ओएनजीसी, हिंडाल्को, टीसीएस , बजाज ऑटो, डॉलर के मुकाबले रुपये में शानदार रिकवरी रही। इससे पहले आज सुबह बाजार की तेजी के साथ शुरुआत रही।

सुबह के शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 835 अंकों की बढ़त के साथ 76,250 के स्तर पर खुला। इसी तरह निफ्टी भी 247 अंक चढ़कर 23,967 पर पहुंच गया। एशियाई बाजारों से मिले मजबूत संकेतों ने भी भारतीय बाजार में को बल मिला।

बकरीद पर 28 मई को भारतीय शेयर बाजार बंद रहेगा

मुंबई ।

भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए यह सप्ताह अहम रहने वाला है। केंद्र सरकार ने बकरीद (ईद-उल-अजहा) के उपलक्ष्य में आगामी गुरुवार, 28 मई को गजेटेड हॉलिडे घोषित कर दिया है। इस घोषणा के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर इस दिन कोई ट्रेडिंग नहीं होगी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब इक्विटी, डेरिवेटिव्स और अन्य सभी सेगमेंट में निवेश करने वाले अपनी खरीद-बिक्री की रणनीति में बदलाव करेंगे। गौरतलब है कि मई का महीना पहले से ही निवेशकों के लिए छुट्टियों भरा रहा है, जिसकी शुरुआत 1 मई के अवकाश से हुई थी। 28 मई की छुट्टी के बाद, 30 और 31 मई को वीकेंड होने के कारण निवेशकों को लंबा अवकाश मिलेगा। हालांकि, इस दौरान अमेरिका, यूरोप और एशियाई बाजारों में सामान्य ट्रेडिंग जारी रहेगी, इसलिए वैश्विक घटनाक्रमों पर नज़र बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा।

भू-राजनीतिक नरमी से क्रिप्टो बाजार में उछाल, बिटकॉइन 77,325 डॉलर पार

मुंबई ।

पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव में नरमी के संकेतों के बाद क्रिप्टो करेंसी बाजार में दूसरे दिन भी तेजी जारी है। प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन 77,325.74 डालर के स्तर पर पहुंच गया है। इस सकारात्मक बदलाव के कारण निवेशकों का रुझान जोखिम वाली संपत्तियों की ओर बढ़ा है। ईरान और अमेरिका के बीच संभावित शांति समझौते और भू-राजनीतिक तनाव कम होने की उम्मीद ने वैश्विक बाजारों को प्रभावित किया है। सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में 5 फीसदी से अधिक की गिरावट दर्ज की गई, जबकि क्रिप्टो बाजार में रौनक लौट आई। भारतीय समयानुसार सुबह 11:50 बजे बिटकॉइन 77,325.74 डॉलर पर ट्रेड कर रहा था, जो रविवार को 76,688 डॉलर के आसपास था। पिछले 24 घंटों में इसने 0.75 फीसदी की वृद्धि दर्ज की है, जबकि इसके पिछले कारोबारी दिन दोपहर से पहले 1.64 फीसदी की तेजी देखी गई थी। हालांकि, ईरान के हालिया बयान ने बाजार में नई अनिश्चितता पैदा कर दी है, जिसमें कहा गया है कि यदि अमेरिका उसकी फीज की गई संपत्ति को रिलीज नहीं करता है तो युद्धविराम विफल हो सकता है।

तिमाही नतीजे से आयशर मोटर्स के शेयरों में 5.8 फीसदी की तेजी, निवेशक खुश

कंपनी का प्रदर्शन मार्च क्वार्टर में उम्मीद से बढ़कर अच्छा रहा

नई दिल्ली।

रॉयल इनफील्ड बनाने वाली आयशर मोटर्स के शेयरों की कीमतों में सोमवार को 5.8 फीसदी की तेजी आई। कंपनी के शेयरों में तेजी के पीछे की वजह तिमाही नतीजे हैं, जिससे निवेशक काफी खुश हैं। जीएसटी कटौती की वजह से इस कंपनी का प्रदर्शन मार्च क्वार्टर के दौरान उम्मीद से बढ़कर अच्छा रहा। बीएसई में सोमवार को आयशर मोटर्स के शेयर बढ़त के साथ 7200.10 रुपए के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 5.8 फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ 7389.55 रुपए के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए थे।

आयशर मोटर्स ने बताया कि मार्च तिमाही में प्रॉफिट 1519.95 करोड़ रुपए रहा है। सालाना आधार पर आयशर मोटर्स का प्रॉफिट 11.58 फीसदी बढ़ा है। पिछले वित्त वर्ष के इसी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 1362.15 करोड़ रुपए था। जनवरी से मार्च तिमाही के दौरान कंपनी का रेवन्यू से 6080.09 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 5241.11 करोड़ रुपए रहा था। बता दें, मार्च क्वार्टर के दौरान रॉयल इनफील्ड की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। कंपनी ने कुल 313811 यूनिट बाइक बेची है।

पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो आयशर मोटर्स का प्रॉफिट 16.5 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 5515.23 करोड़ रुपए रहा।

वित्त वर्ष 2026 में कंपनी का रेवन्यू से 24 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद 23407.56 करोड़ रुपए रहा है। आयशर के शेयरों के

प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स बुलिश हैं।

गोल्डमेन सेसे ने 8400 रुपए का टारगेट प्राइस सेट किया है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बाय रेटिंग दी गई है। वहीं, सीएलएसए ने 7651 रुपए का टारगेट प्राइस सेट किया है।

इस ब्रोकरेज हाउस ने आउटपरफॉर्म रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस एचएसबीसी ने 8200 रुपए का टारगेट प्राइस आयशर मोटर्स के शेयरों के लिए दिया है। बीते एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 35 फीसदी से ज्यादा देखने को मिली। इस कंपनी ने 3 साल में निवेशकों को 101 फीसदी का रिटर्न दिया है।

पाकिस्तान-श्रीलंका से कम बढ़ी भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें

पाकिस्तान, श्रीलंका, यूएई, फिलीपींस और नेपाल में 30 से 86 फीसदी तक की बढ़ोतरी

नई दिल्ली ।

देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर बढ़ाई गई हैं, जो 10 दिनों में चौथी वृद्धि है। हालांकि, यह बढ़ोतरी पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार जैसे कई पड़ोसी देशों की तुलना में काफी कम है, जहां ईंधन के दाम आसमान छू रहे हैं। सोमवार की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर हो गया है। बीते 10 दिनों में पेट्रोल 7.35 रुपये और डीजल 7.53 रुपये महंगा हुआ है। इसके विपरीत म्यांमार में पेट्रोल 90 फीसदी और डीजल 110 फीसदी तक महंगा हुआ है। पाकिस्तान, श्रीलंका, यूएई, फिलीपींस और नेपाल जैसे देशों में भी 30 से 86 फीसदी तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यूरोपीय यूनियन में तो पेट्रोल 180 रुपये और डीजल 184 रुपये प्रति लीटर के औसत भाव पर बिक रहा है, जो भारत से कहीं अधिक

है। यह बढ़ोतरी तेल कंपनियों को हो रहे भारी घाटे को कम करने के लिए की जा रही है। यूक्रेन युद्ध के कारण 76 दिनों तक कीमत न बढ़ने से कंपनियों को रोजाना 1000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा था, जो अब घटकर 500 करोड़ रुपये रह गया है।

भारत में सोने का शौक बना अर्थव्यवस्था की चुनौती

नई दिल्ली।

भारत में सोना सदियों से भरोसे और सुरक्षा का प्रतीक रहा है, पर अब इसकी भारी खरीददारी देश की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बन गई है। विशेषज्ञ बढ़ते आयात बिल और कमजोर रुपये के मद्देनजर सोने को परंपरा नहीं, बल्कि जरूरत और निवेश के नजरिए से देखने की सलाह दे रहे हैं, ताकि खरीददारी का तरीका बदला जा सके। भारतीय परिवारों के पास अनुमानित 34,600 टन सोना मौजूद है, लेकिन भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। इससे चालू खाता घाटा बढ़ता है और रुपये पर दबाव आता है, जो कच्चे तेल की कीमतों के साथ मिलकर आर्थिक दबाव बढ़ाता है। इसी कारण, हाल ही में प्रधानमंत्री ने लोगों से अनावश्यक सोना खरीद टालने की अपील की थी। विशेषज्ञों का मानना है कि लोग अक्सर गहना, निवेश और केवल मुनाफे के लिए की जाने वाली ट्रेडिंग के बीच अंतर नहीं कर पाते। पारंपरिक ज्वेलरी खरीद में मेकिंग चार्ज, जीएसटी और शुद्धता का आकलन मुश्किल होता है।

ईंधन मूल्य वृद्धि से चमके तेल विपणन कंपनियों के शेयर

एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी के शेयरों में 4 से 6 प्रतिशत का उछाल

नई दिल्ली ।

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के बाद सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के शेयरों में जोरदार तेजी दर्ज की गई। कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर कंपनियों के मुनाफे की उम्मीद पर पड़ा, जिससे निवेशक आकर्षित हुए। बीएसई पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) का शेयर 5.86 प्रतिशत बढ़कर 412.55 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गया। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) में 4.55 प्रतिशत और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) के शेयर में 4.15 प्रतिशत की बढ़त देखी गई। यह तेजी सोमवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2.61 से 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के तुरंत बाद आई, जो दो सप्ताह से भी कम समय में चौथी वृद्धि है। 15 मई से अब तक कुल 7.5 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हो चुकी है, जिससे महंगाई और परिवहन लागत बढ़ने की चिंताएं

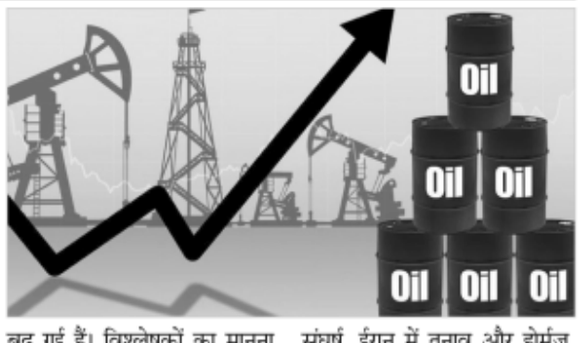

बढ़ गई हैं। विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में फरवरी के अंत से अब तक 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। अमेरिका-इजराइल संघर्ष, ईरान में तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य से आपूर्ति बाधित होने की आशंका इसकी मुख्य वजहें हैं, जो कच्चे तेल को महंगा कर रही हैं।

सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत 76,000 करोड़ का अधिकांश फंड किया गया उपयोग

धोलेरा में डिस्प्ले फैब को मिली मंजूरी, 22 महीनों में पहली माइक्रो-एलईडी स्क्रीन का लक्ष्य

नई दिल्ली ।

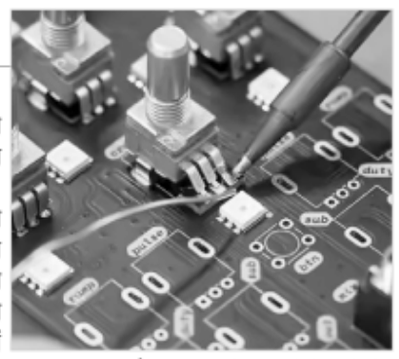

भारत के महत्वाकांक्षी इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के तहत निर्धारित लगभग 76,000 करोड़ रुपये के अधिकांश फंड का उपयोग कर लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस साल देश में माइक्रो-एलईडी पैनल और माइक्रोचिप से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू होने वाली हैं, जो भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करेंगी। सेमीकंडक्टर नीति के तहत, गुजरात के धोलेरा में माइक्रो-एलईडी तकनीक लाने के लिए एक डिस्प्ले फैब को हाल ही में मंजूरी मिली है। मंत्री के अनुसार यह भारत के डिस्प्ले इकोसिस्टम के लिए एक उल्लेखनीय अवसर है। वैश्विक डिस्प्ले उद्योग में ज्योमेट्री के आकार में तेजी से कमी आ रही है, और 50 माइक्रोन पर माइक्रो-एलईडी उपयोगकर्ता अनुभव और कीमत दोनों में एलसीडी व ओएलईडी के साथ सीधे प्रतिस्पर्धी बन जाता है। धोलेरा संयंत्र में मिनी-एलईडी और माइक्रो-एलईडी दोनों तकनीकें इस्तेमाल होंगी, जिसमें माइक्रो-एलईडी चिप का आकार 30 माइक्रोन गुणा 60 माइक्रोन होगा। उम्मीद है कि इस संयंत्र से पहली माइक्रो-एलईडी स्क्रीन लगभग 22 महीनों में तैयार हो जाएगी। सरकार माइक्रो-एलईडी को आज की तकनीक मानती है और इसमें भारत के लिए आगे बढ़ने का अवसर देखती है। रणनीति में प्रौद्योगिकी को साबित करना, आपूर्ति श्रृंखला बनाना, कार्यबल को प्रशिक्षित करना और फिर विस्तार करना शामिल है। इस लक्ष्य के साथ, भारत 2035 तक सेमीकंडक्टर विनिर्माण में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल होने की राह पर है, जिसमें डिस्प्ले निर्माण एक अहम हिस्सा है। सरकार भविष्य में विस्तार के लिए अतिरिक्त सहायता देने को भी तैयार है।

जून में रेपो दर स्थिर रख सकता है आरबीआई सर्वेक्षण

चालू वित्त वर्ष में दरों में बढ़ोतरी की संभावना

नई दिल्ली ।

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और आपूर्ति श्रृंखला में संभावित व्यवधानों से उत्पन्न महंगाई की आशंका के बावजूद, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) अपनी आगामी बैठक 3-5 जून में रेपो दर को वर्तमान स्तर पर यथावत बनाए रख सकती है। एक सर्वेक्षण में अधिकांश प्रतिभागियों ने यह उम्मीद जताई है। हालांकि, सर्वेक्षण में शामिल लगभग सभी विशेषज्ञों ने मौजूदा वित्त वर्ष में कम से कम एक बार दर वृद्धि की संभावना व्यक्त की है, जो ब्याज दरों के रुख में जल्द बदलाव का संकेत देता है। विश्लेषकों का मानना है कि खुदरा मुद्रास्फीति का आरबीआई के लक्ष्य (4 फीसदी) से नीचे बने रहना और पश्चिम एशिया संघर्ष के विकास दर पर संभावित नकारात्मक प्रभाव, केंद्रीय बैंक को प्रतीक्षा करो और देखो की रणनीति अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।

एचडीएफसी बैंक की एक अर्थशास्त्री के अनुसार, मौजूदा हालात में आरबीआई के लिए स्थिति पर नजर रखना सबसे उपयुक्त होगा। अप्रैल में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति मामूली बढ़कर 3.48 फीसदी हो गई, जो मार्च में 3.40 फीसदी थी, मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के कारण। हालांकि, यह अभी भी आरबीआई के 2 से 6 फीसदी के वहनीय दायरे में है। सर्वेक्षण के प्रतिभागियों का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में रेपो दर में एक से लेकर तीन बार तक वृद्धि हो सकती है। उम्मीद है कि एमपीसी जून से नीतिगत दरों में वृद्धि शुरू कर देगी, जिससे वित्त वर्ष 2027 में कुल 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी होगी।

इसका कारण जिंसों के ऊंचे दाम और रुपये पर बढ़ता दबाव है, जिसने पिछले एक साल में डॉलर के मुकाबले 10 फीसदी से अधिक की गिरावट देखी है, जिससे मुद्रास्फीति का जोखिम बढ़ गया है। आरबीआई का मुद्रास्फीति लक्ष्य का लचीला ढांचा उसे आपूर्ति-पक्ष के झटकों को नजरअंदाज करने की गुंजाइश प्रदान करता है, जब तक कि मुद्रास्फीति 6 फीसदी की ऊपरी सीमा से नीचे रहती है।

उपभोक्ताओं को अब मिलेगा पूरा ईंधन, डिस्पेंसर जांच के बदले नियम

नई दिल्ली ।

केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशनों पर उपभोक्ताओं को सही मात्रा में ईंधन सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब सरकारी मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्र (जीएटीसी) इन वितरण मशीनों की जांच कर उनकी सटीकता की पुष्टि करेंगे। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल के साथ-साथ सीएनजी, एलपीजी, एनएनजी और भविष्य के ईंधन हाइड्रोजन डिस्पेंसरों की सटीक माप सुनिश्चित करने के लिए कानूनी माप विज्ञान नियमों में संशोधन किया है। इस बदलाव के बाद, अब सरकारी मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्र इन सभी ईंधन वितरण मशीनों की जांच करेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को मिलने वाली मात्रा में पारदर्शिता और सटीकता बढ़ेगी। पहले जीएटीसी केवल 18 प्रकार के उपकरणों की जांच करते थे, लेकिन पांच नए ईंधन वितरण तंत्रों को शामिल करने के बाद यह संख्या बढ़कर 23 हो गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ईंधन वितरण में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाना, राज्यों के विभागों पर बढ़ते दबाव को कम करना और स्वच्छ ईंधन के बढ़ते चलन के बीच उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा करना है। नए नियमों के तहत पेट्रोल-डीजल डिस्पेंसर की जांच के लिए प्रति

नोजल 5 हजार रुपये और अन्य ईंधन के लिए 10 हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे निजी प्रयोगशालाओं की भागीदारी बढ़ेगी और जांच प्रक्रिया में तेजी व दक्षता आने की उम्मीद है।

कंचनजंगा सिक्किम की चेतना और विरासत का प्रतीक : प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली ।

सिक्किम के राज्य गठन के 51वें वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की सराहना करते हुए कंचनजंगा को सिक्किम की भूमि, स्मृतियों और चेतना का रक्षक बताया है। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए कहा कि कंचनजंगा केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं, बल्कि सिक्किम की पहचान, आस्था और विकास यात्रा का महत्वपूर्ण प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा कि सिक्किम अपने राज्यत्व के 51वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और इस अवसर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कंचनजंगा के महत्व को बेहद संवेदनशील और प्रेरणादायक ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेख में कंचनजंगा के पांच खजानों का उल्लेख किया गया है, जो सिक्किम की प्रगति और 'विकसित सिक्किम 2047' की दिशा में मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने लेख में लिखा कि कंचनजंगा का नाम आते ही हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां, प्रार्थना झंडे और बादलों से घिरी पर्वत श्रृंखलाएं आंखों के सामने उभर आती हैं। उन्होंने बताया कि सिक्किम की लगभग एक चौथाई भूमि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है और यह क्षेत्र सदियों से स्थानीय समुदायों की आस्था और लोककथाओं का केंद्र रहा है। महान लामा ल्हात्सुन चेनपो ने कंचनजंगा की पांच चोटियों को 'शाश्वत बर्फ के पांच खजाने' बताया था, जिनमें सोना, चांदी, रत्न, अनाज और पवित्र ग्रंथ शामिल हैं। सिंधिया ने कहा कि पहला खजाना सोना सिक्किम के लोगों और उनकी सामाजिक एकता का प्रतीक है। लेपचा, भूटिया और नेपाली समुदायों के बीच सामंजस्य और सद्भाव राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य का विकास तभी स्थायी हो सकता है, जब उसमें सामाजिक विश्वास और सामूहिक सहभागिता हो। उन्होंने बताया कि दूसरा खजाना चांदी सिक्किम की

प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता को दर्शाता है। तीस्ता और रंगीत नदियां, घने जंगल, फहाड़ी ढलानों पर फैले चाय बागान और जैविक वातावरण राज्य को विशिष्ट पहचान देते हैं।

शोपियां में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, प्रतिबंधित संस्थान और जमात से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी

श्रीनगर ।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की। इनमें हाल ही में अवैध घोषित किए गए दारुल उलूम सिराजुल उलूम और प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के पूर्व प्रमुख शहजादा औरंगजेब का घर शामिल है। सुरक्षा एजेंसियों की इस कार्रवाई को घाटी में संदिग्ध आतंकी फंडिंग और कट्टरपंथी नेटवर्क के खिलाफ अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार एनआईए की टीम ने तड़के शोपियां के इमाम साहिब इलाके में स्थित दारुल उलूम सिराजुल उलूम में दबिश दी। यह दक्षिण कश्मीर के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में गिना जाता है, जहां बड़ी संख्या में छात्र आधुनिक शिक्षा के साथ धार्मिक अध्ययन भी करते हैं। पिछले महीने प्रशासन ने इस संस्थान को अवैध इकाई घोषित किया था। जांच एजेंसियों को इसके कुछ प्रतिबंधित संगठनों से संभावित संबंधों के संकेत मिले थे, जिसके बाद इसकी गतिविधियां निगरानी में थीं।

इसी दौरान एनआईए की दूसरी टीम ने शोपियां जिले के मोलू चित्रगाम इलाके में स्थित शहजादा औरंगजेब के आवास पर भी छापा मारा। शहजादा औरंगजेब प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। अधिकारियों ने सुरक्षा बलों की मौजूदगी में घर की तलाशी ली और कई दस्तावेजों व डिजिटल उपकरणों की जांच की। सूत्रों का कहना है कि जांच एजेंसी को कुछ महत्वपूर्ण सामग्री मिली है, जिसे जांच के लिए जब्त किया गया है। सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई घाटी में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को समर्थन देने वाले नेटवर्क को

तोड़ने के उद्देश्य से की जा रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि कुछ संस्थानों और व्यक्तियों के माध्यम से युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रभावित करने और प्रतिबंधित संगठनों के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिशें की जा रही थीं। इसी संदर्भ में वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध संपर्कों की भी जांच की जा रही है।

अधिकारियों ने फिलहाल मामले में विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस जांच के आधार पर और भी कार्रवाई हो सकती है। घाटी में सुरक्षा एजेंसियां लगातार ऐसे नेटवर्क पर नजर बनाए हुए हैं, जिन्हें आतंकी गतिविधियों से जोड़कर देखा जा रहा है। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है।

गंगा दशहरा पर भरतपुर के ऐतिहासिक गंगा मंदिर में होगी भव्य आरती

मंदिर को मिलेगा नया मुख्य द्वार

भरतपुर ।

राजस्थान के भरतपुर स्थित ऐतिहासिक गंगा मंदिर में इस बार गंगा दशहरा पर्व विशेष महत्व के साथ मनाया जाएगा। मंदिर अपनी स्थापना के 181 वर्ष और मां गंगा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के 89 वर्ष पूरे कर रहा है। इस अवसर पर मंदिर के मुख्य द्वार और अधूरे शिखर के निर्माण सहित कई विकास कार्य शुरू किए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन कार्यों के लिए नौ करोड़ 57 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। भरतपुर विकास प्राधिकरण की देखरेख में यह निर्माण कार्य अगले 15 महीनों में पूरा किया जाएगा। गंगा दशहरा के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गंगा मंदिर में आयोजित महाआरती में शामिल होंगे। इसके अलावा सुजान गंगा नहर पर दीपदान कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस बार गंगा दशहरा पर कई शुभ योग बन रहे हैं, जिससे पर्व का महत्व और बढ़ गया है। मंदिर की पुरानी परंपरा के अनुसार गर्भगृह में रखी चांदी की नक्काशीदार बोतल में गंगाजल भरकर श्रद्धालुओं को प्रसाद स्वरूप वितरित किया जाता है। गंगा मंदिर भरतपुर के ऐतिहासिक लोहागढ़ दुर्ग के निकट स्थित है और इसका निर्माण बंशी पहाड़पुर के लाल-सफेद बलुआ पत्थर से कराया गया था। मंदिर के निर्माण की शुरुआत तत्कालीन महाराजा बलवंत सिंह ने वर्ष 1845 में कराई थी। कहा जाता है कि उन्होंने हरिद्वार में पुत्र प्राप्ति की मनौती पूरी होने पर इस मंदिर की नींव रखी थी। बाद में महाराजा सवाई बृजेन्द्र सिंह ने वर्ष 1937 में मां गंगा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कराई। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी स्थापत्य कला है। करीब 18 फीट ऊंचाई पर बने इस मंदिर को 80 नक्काशीदार स्तंभों का सहारा प्राप्त है।

कई राज खोलती शिवराज की किताब अपनापन

नई दिल्ली।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की नई पुस्तक अपनापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके तीन दशकों से अधिक पुराने आत्मीय संबंधों और अनुभवों का हृदयस्पर्शी वर्णन किया गया है। 26 मई को नई दिल्ली में विमोचित होने वाली इस पुस्तक में 1991-92 की एकता यात्रा से लेकर वर्ष 2025 तक के कई महत्वपूर्ण संस्मरण शामिल हैं। शिवराज सिंह चौहान ने पुस्तक में लिखा है कि 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश में मोहन यादव के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पास आए और धीरे से कहा था, शिवराज, समय निकालकर दिल्ली आओ। आपसे कुछ बातें करनी हैं। इसके छह महीने बाद जून 2024 में जब उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली, तब उन्हें अहसास हुआ कि प्रधानमंत्री ने उस समारोह के दौरान ही उनके लिए भविष्य की योजना बना ली थी। पुस्तक में अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम

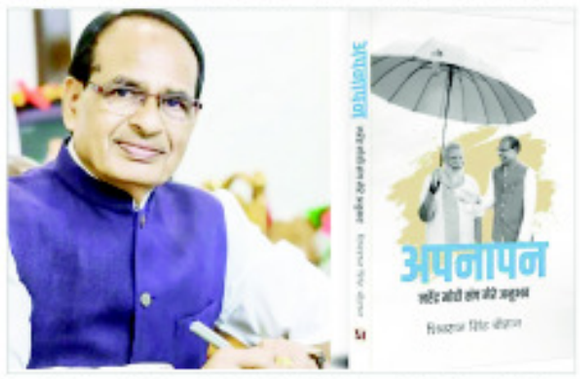

हमले के बाद की एक कैबिनेट बैठक का भी जिक्र है। चौहान ने लिखा कि उस कठिन समय में भी प्रधानमंत्री बेहद शांत और दृढ़निश्चयी थे। पीएम मोदी ने तब स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इस बार का ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक से अलग होगा और दोषियों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर सजा दी जाएगी। इसके अलावा, किताब में 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय का एक भावुक वाकया भी साझा किया गया है। चुनाव प्रचार के दौरान जब शुरुआती सूचियों में चौहान का नाम नहीं था, तब विपक्ष ने उनके एक बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया और यह प्रचारित किया कि उनका राजनीतिक करियर समाप्त हो गया है। इस कठिन समय में प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से फोन किया। पीएम ने उन्हें मुख्यमंत्री के बजाय अपने शिवराज कहकर संबोधित किया और बहुत गर्मजोशी से पूछा, आप इतने चिंतित क्यों हो? कुछ समय एकांत में बिताएं और अपने मन को शांत रखें। प्रधानमंत्री की सलाह मानकर शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड में ऋषिकेश के पास गंगा किनारे कुछ समय बिताने गए, जिससे उनका मन शांत हुआ।

भारत में 115 साल पहले शुरु हो चुकी थी निजी विमान रखने की परंपरा

नई दिल्ली ।

बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में निजी विमान रखने की शुरुआत करीब 115 साल पहले हो चुकी थी। इस शाही परंपरा की नींव पटियाला रियासत के महाराजा भूपेंद्र सिंह ने रखी थी, जिन्हें अपने समय का सबसे अमीर और आधुनिक सोच वाला राजा माना जाता था। महाराजा भूपेंद्र सिंह का जन्म 12 अक्टूबर 1891 को हुआ था। उन्होंने मात्र नौ साल की उम्र में पटियाला रियासत की गद्दी संभाल ली थी। उस दौर में दुनिया में विमानन तकनीक शुरुआती चरण में थी और हवाई जहाज लोगों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं थे। ऐसे समय में साल 1910 में महाराजा भूपेंद्र सिंह ने फ्रांस से अपने लिए निजी विमान मंगवाए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने प्रसिद्ध मोती बाग महल के बाहर एक निजी हवाई पट्टी और रनवे भी बनवाया

था। इसे भारत का पहला निजी एयरफील्ड माना जाता है। महाराजा जब चाहते, अपने विमानों से उड़ान भरते थे। उनके इस कदम को आज के प्राइवेट जेट कल्चर की शुरुआती कड़ी माना जाता है। महाराजा भूपेंद्र सिंह अपनी बेशुमार दौलत और शाही ठाठ-बाट के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। उनकी शान का सबसे बड़ा प्रतीक 'पटियाला नेकलेस' माना जाता है। साल 1925 में उन्होंने पेरिस की मशहूर ज्वेलरी कंपनी कार्टियर को दुनिया का सबसे शानदार हार बनाने का आदेश दिया था। तीन वर्षों की मेहनत के बाद 1928 में तैयार हुए इस हार में करीब 2,930 हीरे जड़े गए थे। इसका सबसे खास आकर्षण 234.6 कैरेट का 'डी बीयर्स' हीरा था, जिसे दुनिया के सबसे बड़े हीरों में गिना जाता है। इस हार की अनुमानित कीमत आज करीब 248 करोड़ रुपये बताई जाती है।

हालांकि साल 1948 में यह ऐतिहासिक हार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझ सकी है। महाराजा को लग्जरी कारों का भी बेहद शौक था। कहा जाता है कि उनके पास 27 रॉल्स रॉयस कारों का काफिला था। इनमें कई कारें विशेष रूप से उनके आदेश पर तैयार कराई गई थीं। उनके खान-पान और रहन-सहन की कहानियां भी काफी चर्चित थीं।

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, फिर भी आम आदमी की जेब काट रही सरकार

कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने पेट्रोल-डीजल कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर हमला बोला

नई दिल्ली।

कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोमवार को पेट्रोल-डीजल कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद वह आम आदमी की जेब काट रही है। सुरजेवाला ने कहा कि आज कच्चे तेल की कीमत गिरकर 98.6 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गई है। बीजेपी पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में 2.71 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करके आम आदमी की जेब काट रही है। हमारे पास इस बारे में एक बड़ा खुलासा है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक कच्चे तेल के बाज़ारों में लगातार उतार-चढ़ाव और पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के बीच, दो हफ़्ते से भी कम समय में यह चौथी बढ़ोतरी है। ताज़ा संशोधन के बाद, दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के आंकड़े को पार कर गईं, इसमें 2.61 रुपए की बढ़ोतरी हुई और यह 102.12 रुपए प्रति लीटर हो गया, जबकि डीज़ल की कीमतों में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई और यह 95.20 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भी इसी तरह की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे उपभोक्ताओं और परिवहन संचालकों पर बोझ और बढ़ गया है।

कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के दिल्ली के निर्धारित दौरे के बारे में पूछे जाने पर, सुरजेवाला ने बैठक के उद्देश्य को लेकर लगाई जा रही अटकलों को खारिज कर दिया और इसे राज्यसभा चुनावों को लेकर पार्टी के चल रहे विचार-विमर्श से जोड़ा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनावों की अधिसूचना जारी हो चुकी है। पार्टी विचार-विमर्श कर रही है। इसलिए कृपया अटकलें न लगाएं। सीएम सिद्धारमैया मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व से मिलने वाले हैं। राज्य में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर फिर से शुरू हुई अटकलों के बीच, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने सीएम सिद्धारमैया को मंगलवार को दिल्ली बुलाया है।

दिल्ली से यह बुलावा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के तीन साल पूरे होने के मौके पर आया है, और यह ऐसे समय में आया है जब सीएम पद को लेकर सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही है। सूत्रों ने बताया कि इस दौरे के दौरान सीएम सिद्धारमैया राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। इस बात की संभावना है कि सीएम आगामी राज्यसभा चुनावों पर चर्चा करेंगे। इस बैठक के असली मकसद को

लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बैठक में आगामी विधान परिषद चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा हो सकती है। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि पिछले तीन सालों से एक ही बात दोहराई जा रही है।

मुंबई-आगरा हाईवे कई वाहन टकराए, टोल कर्मचारी समेत 6 की मौत, 26 घायल

हादसा धुले के लालिंग घाट में हुआ, सबसे पहले डंपर-ट्रक आपस में भिड़े थे

धुले।

मुंबई-आगरा हाईवे पर कई वाहनों की टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई जबकि 26 घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसा सोमवार तड़के धुले के लालिंग घाट में हुआ। सबसे पहले एक डंपर-ट्रक आपस में टकरा गए। हादसे के बाद टोल कर्मचारी और स्थानीय लोग घायलों को बचाने में जुटे थे। तभी मध्य प्रदेश से आ रही एक तेज रफ्तार यात्री बस बेकाबू हो गई और पहले से क्षतिग्रस्त वाहनों से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बचाव कार्य में जुटे एक टोल कर्मचारी की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट में पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस हादसे में टोल कर्मचारी समेत कुल छह लोगों की मौत हो गई जबकि 26 घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए। घायलों को सुरक्षित निकालकर तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे के कारण हाईवे पर कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

लातूर में छात्रा ने अपने ही खेत में पेड़ पर फांसी लगाकर दी जान

पिता का दावा-नीट-यूजी परीक्षा रद्द होने से मानसिक तनाव में थी

लातूर।

महाराष्ट्र के लातूर जिले के सूबे गोंडेगांव इलाके में रहने वाली 18 साल की एक छात्रा ने मानसिक तनाव के चलते फांसी लगाकर जान दे दी। वह किसान की बेटी थी। मृतका के पिता का दावा है कि नीट-यूजी परीक्षा रद्द होने के बाद से उनकी बेटी भारी तनाव से गुजर रही थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि यह दर्दनाक घटना 16 मई की सुबह की है। जहा छात्रा ने अपने ही खेत में पेड़ से फांसी लगा ली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ की रिपोर्ट दर्ज की है आगे की जांच जारी है। जानकारी के मुताबिक रविवार को पुलिस को दिए बयान में छात्रा के पिता ने बताया कि उनकी बेटी का सपना डॉक्टर बनने का था। उसने कहा था कि अच्छी तैयारी करने और परीक्षा में संतोषजनक प्रदर्शन करने के बावजूद, परीक्षा रद्द होने की वजह से वह परेशान है। वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित थी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी इस तनाव को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने यह खतरनाक कदम उठाया। बता दें नीट-यूजी परीक्षा का आयोजन 3 मई को भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 केंद्रों पर किया गया था। इस परीक्षा के लिए करीब 23 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। परीक्षा होने के कुछ ही दिनों बाद पेपर लीक और धांधली की शिकायतें सामने आईं। पेपर लीक से जुड़ी जांच और कई तरह की रिपोर्ट्स आने के बाद, सरकार ने 7 मई को नीट परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया था। अब इस परीक्षा को दोबारा 21 जून को करवाने का फैसला लिया गया है।

महाराष्ट्र में 800 फीट गहरी खाई में गिरी कार, आठ युवकों की मौत

पुलिस व प्रशासन टीम बचाव कार्य में जुटी, सभी मृतक सतारा के रहने वाले

महाबलेश्वर।

महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में एक भीषण सड़क हादसे ने आठ लोगों जान चली गई। पोलादपुर-आंबेनळी घाट मार्ग पर एक स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर करीब 800 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसा इतना भीषण था कि वाहन में सवार सभी लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हादसा रविवार देर रात हुआ। रात का अंधेरा और घाट क्षेत्र का दुर्गम रास्ता बचाव कार्य में सबसे बड़ी चुनौती बन गया। सूचना मिलते ही महाबलेश्वर ट्रैकर्स की टीम, पुलिस और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचे। सभी मृतक सातारा जिले के कोरेगांव तहसील के आसगांव गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनमें महेश अनिल पवार (25), आदित्य अशोक सालुंखे (21), रितेश राजेंद्र लोखंडे (25), सुहास जितेंद्र लोखंडे (20), अंश समीर चव्हाण (18), उत्कर्ष आनंद शिंगटे (21), अनिल अभिमन्यू शिंगटे (25) नितीन किसन नायकोंडे (35) शामिल हैं. सुबह करीब छह बजे से चार अलग-अलग रेस्क्यू टीमें युद्धस्तर पर बचाव अभियान में जुटी हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस लगातार घटनास्थल पर मौजूद रहकर राहत कार्य की निगरानी कर रहे हैं। फिलहाल दुर्घटना की असली वजह का पता नहीं चल सका है। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। शुरुआती तौर पर आशंका जताई जा रही है कि घाट मार्ग के खतरनाक मोड़, रात का समय या वाहन के नियंत्रण खोने जैसी परिस्थितियां हादसे की वजह हो सकती है।

किशोरी को अगवा कर तीनों युवकों ने किया गैंगरेप, दो आरोपी गिरफ्तार

एटा ।

उत्तर प्रदेश के एटा जिले के मारहरा थाना क्षेत्र में कथित तौर पर घर के पास नल से पानी भरने गई 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी का अपहरण कर तीन आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इस दौरान विरोध करने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने इस मामले में दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, और तीसरे अज्ञात आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक, घटना शनिवार रात करीब 11 बजे की है। किशोरी अपने भाई को पानी देने के लिए घर के पास लगे नल पर गई थी। आरोप है कि तभी गांव के ही लवकेश उर्फ लब्बा और निरंजन सिंह अपने एक अज्ञात साथी के साथ वहां पहुंचे। आरोपियों ने किशोरी का मुंह दबाकर उसे जबरन गाड़ी में खींच लिया और सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी पीड़िता को बदहवास हालत में छोड़कर फरार हो गए। पीड़िता की मां के मुताबिक, वह अपने बेटे को खाना देकर लौट रही थी, काफी देर तक बेटी के वापस न आने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की, इसके करीब ढाई घंटे बाद किशोरी गंभीर और बदहवास हालत में घर पहुंची और परिजनों को आपबीती बताई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मारहरा पुलिस सक्रिय हुई। सदर क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) संकल्पदीप कुशवाहा ने बताया कि पीड़िता के पिता की शिकायत पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने दोनों नामजद आरोपियों लवकेश और निरंजन को गिरफ्तार कर विधिक प्रक्रिया पूरी कर जेल भेज दिया। मामले की जांच सीओ सदर कर रहे हैं। तीसरे अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक कजोड़मल मीना के लिए स्काईटक प्रिन्टर्स, 111, नवाब कल्लन का बाग, एमएलए क्वार्टर, नीयर समाचार जगत, एमआई रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 303, भव्य टॉवर, कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर से प्रकाशित।
(इस अंक में प्रकाशित समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी) समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर शहर होगा। RNI No. RAJHIN/2001/05699 मो. नं. 9928078717